International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 2, Issue 5, pp: 308-313 www.ijemh.com

भारत–चीन के मध्य राजनीतिक विवाद व उनका वैश्विक प्रभाव

डॉ0 रेखा मेहरा, अस्सिटेंट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग, एम0बी0राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

लोकेन्द्र सिंह भण्डारी, शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग, एम0बी0राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

Date of Submission: 10-11-2021 Date of Acceptance: 26-11-2021

शोध साराँश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारत–चीन के मध्य राजनीतिक विवाद व उनके वैश्विक प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भारत और चीन के मध्य लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। भारत और चीन के संबंधों में सुधार की एक प्रमुख बाधा कई अनिर्णीत क्षेत्रीय दावे एवं सीमा का अतिक्रमण है। चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों से मिलकर बना एक 3,218 किलोमीटर लम्बा मार्ग है, जो कि ग्वादर बंदरगाह को चीन में झिंजियांग से जोड़ेगा। CPEC चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के लिए महत्वपूर्ण है, इस पहल का उद्देश्य चीन को यूरोप और एशिया से जोड़ना है। इस क्षेत्र में किसी भी विवाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। भारत और चीन दोनों एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्जा चाहते हैं जो उनके आकार, शक्ति और क्षमता के अनुरूप हो। दोनों देशों के संबंधों में समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का निर्माण और चीन के साथ शक्ति अंतराल को समाप्त करने की शुरूआत करना आवश्यक है।

Keywords – भारत, चीन, नेपाल, भूटान, CPEC, OBOR, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार।

प्रस्तावना – चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के समय पटेल अहमदाबाद में थे और अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे। उन्होंने अहमदाबाद में कहा कि चीन ने एक देश के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है। कैबिनेट मंत्री सी. राजगोपालाचारी और विदेश सचिव गिरिजा शंकर वाजपेयी भी चीन के खिलाफ थे। दिल्ली लौटने के बाद पटेल ने नेहरू को 7 नवंबर 1950 को खत लिखकर कहा, 'चीन ने हमें शांतिपूर्ण रुख दिखाकर धोखा दिया है। मेरे विचार से चीन की अंतिम कारवाई विश्वासघात है। इसमें त्रासद यह है कि तिब्बत हम पर पूरा भरोसा करता है। वह हमसे संचालित होते हैं। हम उन्हें चीन के प्रभाव से निकालने में पूरी तरह विफल हुए हैं।'

नेहरू ने 18 नवंबर को चीन और तिब्बत के सिलसिले में एक नोट जरूर लिखा, जिसमें पटेल द्वारा उठाए गए मसलों को शामिल किया गया था लेकिन उन्होंने इस संभावना को खारिज किया कि चीन हिमालय से उतरकर भारत पर कभी कोई बड़ा हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम तिब्बत को नहीं बचा सकते लेकिन यह संभव है कि हम कूटनीतिक स्तर पर तिब्बत को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देने पर विचार करें।

15 दिसंबर 1950 को पटेल का निधन हो गया और चीन को लेकर नेहरू का विरोध करने वाला कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था। नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित चीन में भारत की राजदूत बनीं। उन्होंने एक बार माओ और दो बार चाऊ–एन–लाई से मुलाकात की। उन्होंने अपने भाई को लिखा, 'माओ प्रभावशाली और विनोदपूर्ण हैं। चाऊ–एन–लाई एक शानदार राजनेता हैं। हमने साथ में खाया–पिया और संस्कृति और संबंधों पर तब तक बात की, जब तक कि मैं थक नहीं गई।'

उसके बाद नेहरू एक बार फिर काल्पनिक संसार में चले गए। हिंदी–चीनी भाई–भाई का नारा लगा। पंचशील समझौता हुआ और 1959 आते–आते चीन ने दलाई लामा को निर्वासित कर दिया और

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 2, Issue 5, pp: 308-313 www.ijemh.com

उसके 3 साल बाद भारत पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि नेहरू इस सदमे को झेल नहीं पाए और उनका निधन हो गया। उसके बाद से लगातार चीन भारत की सीमाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा चीन की यात्राऐं कीं, चीन से व्यापारिक समझौते किए। वहीं डोकलाम से लेकर गलवान घाटी तक चीन चढ़ा हुआ है। वह भारत–चीन के बीच मैकमोहन रेखा को नहीं मानता और उसका कहना है कि वह औपनिवेशिक काल में थोपी गई थी।

भारत तथा चीन के बीच मुख्य विवाद

आर्थिक और सैन्य शक्तियों के रूप में भारत तथा चीन विश्व के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों राष्ट्रों में कई समान विशेषताऐं हैं एवं यहाँ तक कि एक जैसी ही समस्याऐं भी विद्यमान हैं। इनमें विशाल जनसंख्या, वृहद ग्रामीण–शहरी विभाजन, उभरती अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष शामिल हैं।

1 भारत–चीन सीमा विवाद

भारत की 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा चीन के साथ लगती है। चीन–भारत सीमा को सामान्यतः तीन क्षेत्रों में बांटा गया हैः (i) पश्चिमी क्षेत्र, (ii) मध्य क्षेत्र, और (iii) पूर्वी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में चीन के साथ 2152 कि.मी. लंबी भारतीय सीमा है। यह सीमा जम्मू और कश्मीर तथा चीन के झिंजियांग (सिक्यांग) प्रांत के बीच है। मध्य क्षेत्र में लगभग 625 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लद्दाख से नेपाल तक जल विभाजक (वाटरशेड) के साथ–साथ चलती है। इस सीमा रेखा पर भारत के हिमांचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य, तिब्बत (चीन) के साथ लगते हैं। पूर्वी क्षेत्र में सीमा रेखा 1,140 किमी लंबी है तथा यह भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर भारत, तिब्बत और म्यांमार के मिलन बिंदु, तालू दर्रा के पास तक विस्तृत है। इस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा (हेनरी मैकमोहन के नाम पर) कहते हैं। हेनरी मैकमोहन एक ब्रिटिश प्रतिनिधि थे जिन्होंने 1913–14 के शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे।

अक्साई चिन पर क्षेत्रीय विवाद की जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य की अपने भारतीय उपनिवेश और चीन के बीच कानूनी सीमा की स्पष्ट व्याख्या न करने की विफलता में निहित हैं। ब्रिटिश राज के दौरान भारत और चीन के बीच दो सीमाएं प्रस्तावित की गई थीं – जॉनसन लाइन (Johnson's Line) और मैकडॉनाल्ड लाइन (McDonald Line)। जॉनसन लाइन, अक्साई चिन को भारतीय नियंत्रण में प्रदर्शित करती है जबकि मैकडॉनाल्ड लाइन इसे चीन के नियंत्रण में प्रदर्शित करती है। भारत चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जॉनसन लाइन को सही मानता है जबकि दूसरी ओर, चीन मैकडॉनल्ड लाइन को भारत–चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है। भारतीय–प्रशासित क्षेत्रों को अक्साई चिन से अलग करने वाली रेखा को **वास्तविक नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल : LAC)** के रूप में जाना जाता है और यह रेखा चीन द्वारा दावा की जाने वाली अक्साई चिन सीमा रेखा के साथ समवर्ती है।

भारत और चीन के बीच 1962 में विवादित अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था। भारत का दावा है कि यह कश्मीर का हिस्सा है, जबकि चीन ने दावा किया कि यह झिंजियांग का हिस्सा है।

2 दलाई लामा और तिब्बत

दलाई लामा ने निर्वासन काल में तिब्बती सरकार का गठन किया जो वर्तमान में भी बिना किसी वास्तविक अधिकार के जनता के लिए कार्यरत है। प्रायः भारत और कई अन्य देशों में तिब्बतियों द्वारा चीन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है। चीन ने हाल ही में दलाई लामा की अरूणांचल प्रदेश की यात्रा का विरोध किया। विशेषतः तवांग में, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत मानता है। चीन का मानना है कि दलाई लामा की यात्रा का चीन–भारत संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीन ने भारत पर तिब्बत के विषय में अपनी प्रतिबद्धता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। चीन की चिंताओं को खारिज करते हुए भारत ने लामा की तवांग यात्रा को पूरी तरह धार्मिक बताया है।

3 अरुणांचल प्रदेश और स्टेपल वीजा

भारत के विरुद्ध पहला कदम उठाते हुए चीन ने अरुणांचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल वीजा जारी करना आरम्भ कर दिया था। बाद में चीन द्वारा जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गयी। परंतु अरुणांचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह अब भी जारी है।

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 2, Issue 5, pp: 308-313 www.ijemh.com

4 स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स

- "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स'' भारत को घेरने के उद्देश्य से चीन द्वारा अपनाई गयी एक अघोषित नीति है। इसमें भारत की समुद्री पहुँच (मैरीटाइम रीचेज) के आस–पास बंदरगाहों और नौसेना ठिकानों का निर्माण किया जाना शामिल है।
- चीन कोकोस द्वीप (म्यांमार), चटगांव (बांग्लादेश), हंबनटोटा (श्रीलंका), मारो एटॉल (मालदीव) और ग्वादर (पाकिस्तान) में मौजूद है। विशेष बात यह है कि भारत के अतिरिक्त केवल चीन का ही माले में कार्यात्मक दूतावास है।
- दूसरी तरफ भारत भी चीन के आसपास के देशों के साथ सामरिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- भारत केवल जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ ही नहीं बल्कि चीन के अन्य एशियाई पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में सक्षम हुआ है।

5 नदी जल विवाद

ब्रह्मपुत्र नदी का जल बँटवारा भारत और चीन के मध्य विवाद का एक मुख्य विषय है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र (तिब्बत में सांगपो) नदी के ऊपरी क्षेत्रों में बाँधों (जिक्सू, झांगमू और जियाचा) का निर्माण किया जा रहा है। हालाँकि भारत ने इसके संबंध में आपत्ति व्यक्त की है, परंतु ब्रह्मपुत्र के जल बँटवारे पर कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है।

.6 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह

चीन द्वारा भारत के इस विशिष्ट समूह में प्रवेश के प्रयास को अवरुद्ध किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन, भारत के प्रवेश को अवरुद्ध करके पाकिस्तान के हित में कार्य कर रहा है।

7 आतंकवाद

एक ओर भारत आतंकवादी संगठनों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है तथा पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत मानता है। वहीं दूसरी ओर इस तथ्य के बावजूद चीन हर बार पाकिस्तान का बचाव करता है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जैश–ए–मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के विरुद्ध प्रतिबन्धों के अनुमोदन का प्रयास किया जाता रहा है। चीन ने इन प्रयासों को बाधित किया है।

8 'वन बेल्ट, वन रोड' (OBOR)

बीजिंग में संपन्न हुए वन बेल्ट, वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में देश या सरकार के 29 प्रमुखों और लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। भूटान को छोड़कर, भारत के सभी पड़ोसियों ने इस शिखर सम्मेलन के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। चीन ने वन बेल्ट वन रोड (OBOR) को विश्व के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व (immense economic sense) का बताया और इसे 'सदी के महानतम प्रोजेक्ट (project of the century) के रूप में प्रस्तुत किया।

OBOR पर भारत की आपत्ति

भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) शिखर सम्मेलन से दूर रहकर अपनी चिंताऐं सार्वजनिक कर दी हैं। जैसे-

- पहला कारण, BRI की एक प्रमुख परियोजना **चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** है। यह गलियारा गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा इसमे भारत की **''संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता''** की अनदेखी की गई है। भारत का दावा है कि चीन न केवल भारत की संप्रभुता के प्रति असंवेदनशील है, बल्कि इसने बेल्ट एंड रोड पहल (पहले वन बेल्ट वन रोड कहा गया है) के लिए अपनी योजना का खुलासा भी पूरी तरह नहीं किया है। चीन के एजेंडे में पारदर्शिता की कमी है। भारत का मानना है कि BRI सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन इसे बढ़ावा दे रहा है।

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 2, Issue 5, pp: 308-313 www.ijemh.com

- दूसरा कारण, **BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर** है, जो चीन के नव–उपनिवेशवाद के चरित्र को दर्शाता है। ऐसी परियोजनाएं छोटे देशों को ऋण के चक्र में धकेल सकती हैं, पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती हैं और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

9 चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China-Pakistan Economic Corridor)

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों से मिलकर बना एक 3,218 किलोमीटर लम्बा मार्ग है, जो कि ग्वादर बंदरगाह को चीन में झिंजियांग से जोड़ेगा। CPEC चीन की 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल के लिए महत्वपूर्ण है, इस पहल का उद्देश्य चीन को यूरोप और एशिया से जोड़ना है। चीन ने एक निर्यात जहाज को मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए रवाना करके मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले नव निर्मित ग्वादर बंदरगाह से एक नया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खोला।

भारत – भूटान – चीन

हिमालयी देश भूटान भारत और चीन के मध्य अवस्थित है। विश्व में बड़े राष्ट्रों के पड़ोस में भू–आबद्ध रूप से किसी देश का होना बहुत ही पेचीदगी पूर्ण स्थिति पैदा कर देता है। अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखते हुए भारत के साथ सम्बन्ध प्रगाढ़ किये और चीन के साथ सम्बंधों को आगे बढ़ाने का मार्ग अपनाया। सीमित आर्थिक और सैन्य क्षमताओं के होते हुए भी भूटान का अनूठा राजनीतिक चरित्र कभी औपनिवेशिक प्रभाव में नहीं आया तथा साथ ही दो विश्व युद्धों और शीत युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव से भी स्वयं को बचा कर रखा। तिब्बती संस्कृति, भाषा और इतिहास से गहरा संपर्क होने के कारण तथा वहीं चीन एवं तिब्बत के मध्य विवादित सम्बन्ध होने से इस क्षेत्र में भूटान का भू–सामरिक महत्व में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर भूटान भारत के सम्बन्ध सौहार्दता तथा समझ पर विकसित हुए है जिसने भूटान में संसदीय लोकतंत्र को शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक रूप से अल्प विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भूटान भारत के लिए भू–सामरिक दृष्टि से सर्वोपरि है (विशेष रूप से भारत के 'चिकन नेक कोरिडोर' में अवस्थित होने के कारण तथा यहाँ से नेपाल और बांग्लादेश की दूरी भी कम है), इसके अलावा चीन के साथ विवादित सीमा भी भूटान के भू–सामरिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। चीन के उद्देश्य भूटान में 1960 तक न केवल सीमित और अल्पकालीन रहे, वरन् सीमा विवाद हल न हो पाने के कारण तनावपूर्ण रहे और ऐसा तब तक रहा जब तक 1984 में भूटान ने सीमा सम्बन्धी वार्ता की शुरुआत चीन से नहीं की।

काफी पहले से ही नेपाल और चीन ने भारत को आलम्ब बनाकार अपने अपने हितों को साधा हैं जबकि वहीं भूटान सदैव भारत के समर्थन में खड़ा रहा है। प्रारंभ में भूटान और चीन के सम्बन्ध समस्या ग्रस्त रहे, वर्ष 1954 में "अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइना" में प्रकाशित नक्शे में भूटान के बहुत से क्षेत्र पर चीन ने अपना दावा प्रदर्शित किया, जिसके कारण काफी लम्बे समय तक चले सीमा विवाद की शुरुआत हुई थी। यह नक्शा प्रदर्शित करता है कि "भूटान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र चीन का प्राक् ऐतिहासिक क्षेत्र है।" वर्ष 1950 में ही चीन ने "भूटान को तिब्बत की हथेली की पांच अंगुलियों में से एक माना था।" वर्ष 1958 में चीन ने अपने एक अन्य नक्शे में भूटान की बहुत सी भूमि पर दावा जताया और साथ ही भूटान की लगभग 300 वर्ग किमी भूमि पर कब्जा भी कर लिया। चिंतित भूटान ने इस समय एक दशक पुरानी ब्रिटिश विरासत भारत–भूटान संधि 1949 के अनुच्छेद–2 का सहारा लिया जिसमें कहा गया है कि "इस परिस्थिति में भूटान सरकार ने तय किया कि विदेशी मामलों के संबंध में वह भारत सरकार की सलाह अनुसार निर्देशों का अनुसरण करेगी।"

अभी हाल ही में चीन और नेपाल की नजदीकियाँ सामरिक और व्यापारिक तौर पर बढ़ी हैं तथा चीन अपने पूर्वी तट से भी सामरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में भूटान को अपने आंतरिक घेरे में लेने की अहम कवायद गौर करने लायक है। अब यह पूर्ण रूप से भूटान पर निर्भर करता है कि वह कैसे चीन के इस दबाव का संतुलित विरोध करते हुए अपने बड़े पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम रखता है।

भारत – नेपाल – चीन

नेपाल एक बार फिर से राजनीतिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। किसी न किसी रूप में वहाँ

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 2, Issue 5, pp: 308-313 www.ijemh.com

की राजनीति अस्थिरता का शिकार रही है। इसे चाहे लोकतांत्रिक अपरिपक्वता कहें या फिर चीन की दखलंदाजी या नेपाल की मजबूरी, ताजा गतिरोध नेपाल की संसद भंग होने के साथ शुरू हुआ है। सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली 2017 के आम चुनाव के बाद तब प्रधानमंत्री बने थे, जब उनके नेतृत्व वाली पार्टी सी.पी.एन.–यू.एम.एल. और पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड की पार्टी सी.पी.एन. (माओ सेंटर) के विलय से सरकार बनी। तब से उनके कार्यकाल में कई घटनाऐं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की हुईं। उनके कार्यकाल को असफल माना जा रहा है।

वर्तमान घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में यदि हम जाऐ तो पाते हैं कि प्रधानमंत्री ओली का कार्यकाल विवादों में घिरा रहा है। उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा ही उनका विरोध किया जाता रहा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो ओली किसी न किसी रूप में भारत के साथ संबंधों को और भी खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। चाहे इसे चीनी प्रभाव कहें या ओली की खुद की नीति भारत की मित्रता को उन्होंने धूमिल करने का काम किया। भारत के साथ ओली की कड़वाहट का बीज तब ही पड़ गया था, जब 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ और ओली प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 2016 में ओली के साथ जुड़ी दूसरी पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया जिस कारण ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। ओली ने इस घटना के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि तब भारत ने नेपाल के संविधान पर यह कह कर आपत्ति जताई थी कि उसमें मधेशी और थारु लोगों की मांगों को शामिल नहीं किया था। इस आपत्ति को समझे बिना भारत को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए ओली की कड़वाहट भारत के प्रति बढ़ती गई। अभी हाल में भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद इसी कड़वाहट और चीनी प्रभाव का उग्र रूप था।

भारत–नेपाल के बीच सीमा विवाद का कारण नेपाल द्वारा नया नक्शा जारी करना था। नेपाल सरकार के इस नए नक्शे में कुल 395 वर्ग कि.मी. के दायरे में अपना अधिकार दर्शाया गया था, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा शामिल थे। भारत सरकार के विरोध के बावजूद नेपाल सरकार द्वारा अपने देश का नया राजनीतिक व प्रशासनिक नक्शा जारी करना चिंतनीय था। नए नक्शे में नेपाल जिन इलाकों पर अपना दावा साबित करना चाह रहा था, वास्तव में वे इलाके भारत की सीमा के भीतर थे। पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख तक नई सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। इस सड़क पर भी नेपाल ने आपत्ति जताई थी। प्रत्युत्तर में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए नेपाल की आपत्ति को खारिज करते हुए कड़ा ऐतराज जताया। नेपाल के वर्तमान संकट की स्थिति के संदर्भ में देखें तो भारत के लिए भी एक चुनौती है जिसे बड़ी संवेदनशीलता और कूटनीति के साथ संभालने की जरुरत है।

निष्कर्ष

भारत और चीन दोनों एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्जा चाहते हैं जो उनके आकार, शक्ति और क्षमता के अनुरूप हो। दोनों देशों के संबंधों में समानता स्थापित के लिए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का निर्माण और चीन के साथ शक्ति अंतराल को समाप्त करने की शुरूआत करना आवश्यक है। दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग उन्हें वैश्विक प्रभावों को पुनर्संतुलित करने और विश्व में एक बेहतर समझौता वार्ता स्तर को विकसित करने में समर्थ कर सकता है। चीन और पाकिस्तान पर भारत की विदेश नीति के निर्माण और दृष्टिकोण को अलग–अलग विदेश नीति नियोजन क्षेत्र के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक हाइफेनेटेड (सामासिक) रणनीतिक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। इन मुद्दों को निरंतर वार्ता के माध्यम से हल करना होगा। तत्काल उठाए जाने वाले कदमों में, ट्राई–जंक्शन पर तनाव को कम करने पर केंद्रित वार्ताओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

यह मानने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि चीन एक विस्तावरवादी सोच रखने वाला राष्ट्र है जो काफी समय से अपनी विस्तारवादी नीति पर चलकर अपने आस–पास स्थित राष्ट्रों की जमीन पर अपना प्रभुत्व जमाने की हरसंभव कोशिशें करता आ रहा है जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रहा है। तिब्बत इसका परोक्ष उदाहरण है, भले ही इतिहासकार यह मानते आए हैं कि इसमें नेहरु की संकुचित सोच एक बड़ा कारण थी लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ परोक्ष–अपरोक्ष रुप से नेहरु और मनमोहन सिंह की सरकार का अनुकरण करती दिखाई पड़ती हैं। इन नीतियों का खामियाजा अतीत में भी भारत को

भुगतना पड़ा था जब लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत के हाथ से निकल गया था। अब चीन पाकिस्तान और नेपाल की मदद से फिर से अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत भारत की प्रभुत्ता वाले क्षेत्रों पर अपना हक जताने की फिराक में लगा है जोकि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ऐसे में भारत को चीन के साथ अपनी विशिष्ट शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान निकालना चाहिए। अपनी चिंताओं को अन्य भागीदार देशों के साथ और अधिक प्रभावी तरीके से व्यक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को बेहतर संपर्क (connectivity) स्थापित करने के प्रयास से बाहर रहने के बजाय स्वयं को एशियाई नेता के रूप में स्थापित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. Ahsan, Syed Aziz-al and Bhumitra Chakma. "Bhutan's Foreign Policy: Cautious Self Assertion?" *Asian Survey*. (USA: University of California Press, 1993), pp. 1043-1054.

[2]. Basrur, Rajesh. "India and China: A Managed Nuclear Rivalry?." *The Washington Quarterly* 42.3 (2019): 151-170.

[3]. Gnyawali, Kaushal Raj, et al. "Mapping the susceptibility of rainfall and earthquake triggered landslides along China–Nepal highways." *Bulletin of Engineering Geology and the Environment* 79.2 (2020): 587-601.

[4]. Jacob, Jabin T. "Arunachal Pradesh in India-China Relations: Trends in Chinese Behaviour and their Implications." *Tawang, Monpas and Tibetan Buddhism in Transition*. Springer, Singapore, 2020. 153-162.

[5]. Maxwell, Neville. "China and India: The un-negotiated dispute." *China Q.* (1970): 47.

[6]. Menon, Prabhakar. "Tibet: The Last Months of a Free Nation: India Tibet Relations (1947-1962) Part I." *Indian Foreign Affairs Journal* 12.4 (2017): 355-361.

[7]. Ranjan, Alok. "The China-Pakistan economic corridor: India's options." *Institute of Chinese Studies* 10.1 (2015): 1-25.

[8]. S. D. Muni, "Bhutan Steps Out," *The World Today* (London), vol. 40, no. 12, December 1984, p. 515.

[9]. Sauvagerd, Monja. "India's Strategies on its Periphery: A Case Study in the India–Bhutan Relationship." *ASIEN* 146 (2018): 56-77.

[10]. Sebastian, N. "Intrusions and Violation of LAC in India–China Border." *and Democracy* (2020): 22.

[11]. Surjit Mansingh, "China-Bhutan Relations," *China Report* (New Delhi), vol. 30, no. 2, 1994, p. 177.

[12]. Tripathi, Dhananjay. "Influence of Borders on Bilateral Ties in South Asia: A Study of Contemporary India–Nepal Relations." *International Studies* 56.2-3 (2019): 186-200.

[13]. uddin Ahmed, Salik, et al. "China Pakistan Economic Corridor and Pakistan's energy security: A meta-analytic review." *Energy policy* 127 (2019): 147-154.

[14]. इंडिया आफ्टर गांधी – रामचंद्र गुहा, पिकाडोर पब्लिकेशन 2007, पेज 170.